राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड
31वीं बैठक - दिनांक : 19 जनवरी, 2010 का कार्य वृत्त

उत्तराखंड में कार्यरत समस्त बैंकों द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सितम्बर, 2009 तक की प्रगति समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की 31वीं बैठक होटल मधुबन, देहरादून में दिनांक 19 जनवरी, 2010 को आयोजित की गई। बैठक का उद्‌घाटन मुख्य अतिथि माननीय मुख्य मंत्री महोदय उत्तराखंड डा. रमेश पोखरियाल '' निःशंक '' तथा उपस्थित वरिष्ठ अतिथियों के करकमलों से दीप प्रज्जवलित कर सम्पन्न किया गया।

इस बैठक में विशिष्ट अतिथि श्री अजय कुमार जोशी, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त (अवस्थापना), श्री सुभाष कुमार, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त (एफ.आर.डी.सी.), श्री आलोक कुमार जैन, प्रमुख सचिव (वित्त), श्री पी.सी. शर्मा, प्रमुख सचिव (उद्योग एवं औद्योगिक विकास), श्री राकेश शर्मा, प्रमुख सचिव (पर्यटन) उत्तराखंड शासन, श्री सुनील पंत, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, दिल्ली मण्डल एवं श्री पी. दास, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड के साथ राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों तथा वाणिज्यिक / ग्रामीण / सहकारी / निजी बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं / निगमों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया।

मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक का संबोधन -

माननीय मुख्यमंत्री, वरिष्ठ अतिथियों एवं सभी प्रतिभागियों के अभिनन्दन के पश्चात श्री सुनील पंत, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नई ादिल्ली, ने सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत करते हुए प्रदेश में कार्यरत समस्त बैंकों द्वारा राज्य के विकास में योगदान एवं राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारियों के सहयोग हेतु आभार प्रकट किया। उन्होंने इस क्रम में चलाई जा रही विभिन्न ऋण योजनाओं में बैंकों द्वारा सितम्बर, 2009 तक की गई प्रगति से सदन को अवगत कराया।

उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं सदन में उपस्थित प्रतिभागियों का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि ऋण-जमा अनुपात ही प्रदेश की प्रगति का मापदण्ड है, और प्रदेश के सर्वांगीण विकास हेतु ऋण प्रवाह बढ़ाने एवं ऋण ग्रहण क्षमता (Credit Absorption Capacity) सृजित करने की आवश्यकता है। प्रदेश के ऋण प्रवाह में गति लाने के उद्देश्य से इसके लिए कौन-कौन से क्रेडिट इनपुट्स (Credit Inputs) चाहिए , उसका पता लगाया जा सकता है ताकि गरीब जनता के साथ-साथ राज्य के समग्र उत्थान में बैंक सार्थक सहयोग प्रदान कर सके।

उत्तराखंड के नेसर्गिक पर्यावरण में सौगात के रुप में प्राप्त जड़ी-बूटी का दोहन - उत्पादक क्षेत्र को बिना क्षति पहुँचाए, हम पूरे भारत ही नहीं बल्कि विश्व को आयुर्वेदिक औषधि उपलब्ध करा सकते हैं। उत्तराखंड में उद्यान. बागवानी, बेमौसमी एवं जैविक सब्जियों की खेती का वाणिज्यिकरण किया जा सकता है और इनके विपणन हेतु राष्ट्रीय / बहुराष्ट्रीय नेटवर्किंग विकसित किया जा सकता है, क्योंकि अद्यतन अनुसंधानों ने सिद्ध कर दिया है कि विश्व में पौष्टिक जैविक उत्पाद के सेवन से मानव शरीर की कई व्याधियों यहाँ तक कि कैन्सर तक से बचाव किया जा सकता है। उत्तराखंड राज्य के दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों के कृषकों को इस प्रकार की खेती करने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार कर जागरुक करने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के शांतिमय परिक्षेत्र में पठन-पाठन की अपार संभावनाएं हैं, जिसके विकास के लिए आज के परिवेश को देखते हुए संवर्धित वातावरण तैयार करने की आवश्यकता है। उत्तराखंड के लोगों में पर्याप्त बौद्धिक प्रतिभा एवं उनकी सामाजिक / सांस्कृति पहल, जोकि यहाँ एक रिसोर्स बैंक (Resource Bank) है, जिसको प्रदेश के विकास में प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। उत्तराखंड में ई-लर्निंग का व्यापाक प्रसार किया जा सकता है क्योंकि यहाँ **'' बिनजेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग ''** (BPO) के लिए एक नया वातावरण बन रहा है और कई बी.पी.ओ. अन्यत्र से स्थानान्तरित होकर इस प्रदेश में स्थापित हो रहे हैं।

साथ ही उन्होंने उत्तराखंड राज्य में बैकों द्वारा विभेदक ब्याज दर (DRI) के ऋण का प्रतिशत बहुत कम होने पर चिंता व्यक्त की। कई वित्तीय संस्थाओं का कहना है कि विभेदक ब्याज दर के ऋणों की वसूली अच्छी नहीं है इसलिए बैंक डी.आर.आई के ऋण देने से बचते हैं परंतु उन्होने कहा कि यदि लाभार्थी एवं उनके प्रोजेक्ट का चयन सही हो तो इसमें बैंक अपना अच्छा योगदान दे सकते है।

गाँव-गाँव में साहूकारी प्रथा को समाप्त करने की दिशा में भी बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए, कृषकों पर बोझित ऋण को भी ग्रहण (Loan takeover) करने का प्रयास कर सकते हैं।

उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में संशोधन करते हुए बैठक में सम्मिलित होने एवं हमारा मार्गदर्शन करने हेतु पधारने पर आभार प्रकट किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी बैंक समग्र प्रयासों से वार्षिक लक्ष्य को शत प्रतिशत प्राप्त करेंगे।

अंत में उन्होंने बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों का धन्यवाद करते हुए अपना संबोधन पूर्ण किया।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय का संबोधन -

माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उपस्थित प्रतिभागियों का स्वागत एवं शुभकामनाएं प्रदान करते हुए पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों की समीक्षा की तथा सदन को अवगत कराया कि उत्तराखंड पिछड़ा राज्य जरुर है लेकिन इसमें आगे बढ़ने की सबसे अधिक क्षमता है। क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए सभी प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ एवं वित्तीय संस्थाओं के साथ मिलकर सामाजिक, भौतिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए अध्ययन कर, रोजगारपरक नई योजनाएं बनाएं जिसमें स्थानीय जनसाधारण की सहभागिता सुनिश्चित की जा सके। उन्होने कहा कि यदि राज्य की हरिद्वार एव उधम सिंह नगर जिले का ऋण-जमा अनुपात हटा दिया जाए तो राज्य का ऋण-जमा अनुपात बहुत कम रह जाएगा। इसलिए पहाड़ी क्षेत्र के जिलों के ऋण-जमा अनुपात में वृद्धि लाने हेतु उद्यान,. ग्राम्य विकास, कृषि विभाग, नाबार्ड तथा अग्रणी जिला प्रबंधक आपस में चर्चा कर अपने-अपने क्षेत्र की संभाव्यताओं को ध्यान में रखते हुए आधुनिक तकनीक के आधार पर ग्राम्य एवं कृषि विकास की योजनाएं बनाकर चरणबद्ध एवं समयबद्ध रणनीति तैयार कर जिले में लागू करें।

उन्होंने आगे कहा कि राज्य की निर्धारित वार्षिक ऋण योजना के सापेक्ष बैंकों द्वारा उपलब्धि बहुत कम रही है और अब इस वित्तीय वर्ष के समाप्त होने में कुछ ही माह शेष हैं,इसलिए कृषि, उद्योग, उद्यान एवं पर्यटन विभाग बैंकों के साथ बैठकर शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति हेतु योजनबद्ध रणनीति तैयार कर लागू करें।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सदन को अवगत कराया कि प्रदेश की सभी 670 न्याय पंचायत मुख्यालय के ग्रामों में '' **अटल आदर्श ग्राम योजना** '' राज्य के स्थापना दिवस 09 नवम्बर, 2009 के शुभ अवसर पर आरम्भ कर दी गई है। इस योजना को सफल बनाने हेतु राज्य सरकार के विभागों के साथ-साथ सभी बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वह इन ग्रामों में से कुछ को अंगीकृत करते हुए समस्त बैंकिंग सेवाएं / सुविधाएं बैंक शाखा अथवा बिजनेस कोरसपोंडेंट / बिजनेस फेसिलिटेटर के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करवाएं। सभी अग्रणी जिला प्रबंधक, इन आदर्श ग्रामों में कृषि गतिविधियों एवं लघु उद्योगों से जुडी रोजगारोन्मुख परियोजनाओं को नाबार्ड की सहयोग से लागू कर बैंकों द्वारा वित्तपोषण करवाएं।

सरकार द्वारा प्रायोजित ज्यादातर ऋण योजनाएं ग्रामीण क्षेत्र एवं ग्रामीण बेरोजगारों के लिए बनी हैं परंतु शासन, प्रशासन एवं बैंक के बीच संवाद एवं समन्वय के अभाव में जरुरतमदों को लाभ नहीं पहुँच पा रहा है। इस पर आपस मे चर्चा कर समाधाना करने की आवश्यकता है।

राज्य के विकास में उत्तराखंड की महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका एवं भागीदारी है, परंतु बैंकों द्वारा महिलाओं को वित्तपोषण बहुत कम किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर महिला स्वयं

सहायता समूह बने हुए हैं लेकिन उन सभी का बैंक लिंकेज नही हो पाया है। इस दिशा में प्रशासन एवं बैंकों को सार्थक प्रयास करने की आवश्यता है।

उन्होंने कहा कि विश्व में आयुष की राजधानी उत्तराखंड है। राज्य में पंचकर्म, योग एवं आध्यात्म का व्यवसायिक उपयोग नहीं किया जा रहा है। अतिथियों एवं पर्यटकों के तन-मन के शुद्धिकरण हेतु योग एवं आध्यात्म का प्रचार-प्रसार एवं व्यवसायीकरण किया जाना चाहिए। इसी प्रकार राज्य में जड़ी-बूटी की खेती की अपार संभावना को देखते हुए संबंधित विभाग एक ''संयुक्त कोर-टीम'' गठित कर एक कार्ययोजना बनाए। साथ ही उन्होने कहा कि हमारे प्रदेश से जड़ी-बूटी का दोहन इस प्रकार से किया जाए ताकि प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरण भी सुरक्षित रहें।
उन्होंने उत्तराखड राज्य में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के **प्राकृतिक संसाधनों** का उपयोग कर राज्य को एक **आदर्श राज्य बनाने की चुनौती बैंकों** को दी। उन्होंने कहा कि बैंकों द्वारा की गई अब तक की उपलब्धि संजोषजनक तो है किंतु इसमें और तीव्रता लाने की आवश्यकता है। अंत में शुभ कामनाएं और धन्यवाद देते हुए उन्होंने अपना संबोधन समाप्त किया।

श्री अजय कुमार जोशी, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त (अवस्थापना) ने ऋण-जमा अनुपात पर हुई चर्चा की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रदेश में ऊर्जा उत्पादन, संरक्षित एवं विविध (diversified) खेती की प्रबल संभाव्यता का उपयोग करते हुए प्रोजेक्ट तैयार करने चाहिएं।
प्रदेश में जमा राशि बढ़ाने की क्षमता सीमित है परंतु विभिन्न मदों में ऋण प्रवाह की संभावना अपार है। इसलिए बैंकों को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा ऋण वितरित करें। बैंकों की ऋण-जमा अनुपात की उपलब्धि संतोषजनक नहीं है, परंतु हम आशा करते हैं कि आगामी महीनों में बैंक शत प्रतिशत की प्राप्ति कर सकता है।

श्री सुभाष कुमार, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त (एफ.आर.डी.सी.) ने अपने संबोधन में बैंकों से अपेक्षा करते हुए कहा कि सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न ऋणों पर उपलब्ध अनुदान राशि पर भी ब्याज लगाया जा रहा है जिस पर बैंकों द्वारा संशोधन करने की आवश्यकता है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना में प्रस्तावित ग्रामीण इलाकों में ऋण उपलब्ध कराने के लिए होटल निर्माण हेतु नक्शा पास करवाने का प्रावधान नहीं है इसलिए जिस क्षेत्र में नक्शा पास करवाने का प्रावधान हो वहीं पर बैंकों द्वारा अनिवार्यता बताई जाए। ऐसा संज्ञान में आया है कि नए उद्योग स्थापित करने हेतु उद्यमियों को बैंक सीधे ऋण उपलब्ध करवा देते हैं, यदि उनके

आवेदन जिला उद्योग विभाग के माध्यम से मंगवाएं जाएं तो ऋणी अनुदान राशि से भी लाभान्वित हो सकता है। अंत में उन्होने अपने संबोधन में विचार प्रकट किया कि गढ़वाल एवं कुमायूँ क्षेत्र के

कमिशनर को भी राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की बैठक मे आमंत्रित किया जाए ताकि इस बैठक में लिए गए निर्णयों का जनपद स्तर पर कार्यान्वयन किया जा सके।

श्री आलोक कुमार जैन, प्रमुख सचिव (वित्त) ने समस्त बैंक के नियंत्रकों से अनुरोध किया कि वह दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र के ग्रामीणों को उनके निवास स्थान के निकट ही समस्त बैंकिंग एवं वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अपनी शाखा विस्तारीकरण नीति को सरलीकृत करें और जहाँ बैंक शाखा खोलना लाभकारी न हो, वहाँ बिजनेस कारेसेपोंडेंट और बिजनेस फेसिलिटेटर मॉडल को अपनाया जाना चाहिए। हालाँकि इस क्षेत्र में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उत्तराखंड के सीमांत जिलों के ग्रामीणों को बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए '' जीरो मॉस संस्था '' के माध्यम से ''एस.बी.आई. टाइनी '' के नाम से स्मॉर्ट कार्ड की तरह वैकल्पिक चैनल से बैंकिग सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उत्तराखंड के ग्रामीण एवं अर्द्धशहरी क्षेत्रों में व्यवसाय हेतु अपार संभाव्यताएं (Potential) और अवसर उपलब्ध हैं जिन्हें ग्रहण करके प्रोजेक्ट में परिवर्तित करने की आवश्यकता है।

सभा के अंत में **श्री थ्रीश कपूर, अध्यक्ष, उत्तरांचल ग्रामीण बैंक** द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक द्वारा सभी बैंक अधिकारियों को आगामी बैठक हेतु दिसम्बर, 2009 तक के सही एवं पूर्ण आँकड़ों के विवरण दिनांक 10 फरवरी, 2010 तक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, को भेजने हेतु कहा गया तथा उपस्थित विशिष्ट अतिथियों, प्रतिभागियों, प्रेस तथा मीडिया के प्रतिनिधियों द्वारा बैठक को सजीव एवं सफल बनाने हेतु धन्यवाद एवं आभार प्रकट किया गया।

****